Newspaper Clips

September 3-5, 2016

5 September

Financial Express ND 05.09.2016 P-12

IIT Roorkee deploys ERP technology across its three campuses

In a first for any IIT campus in India, IIT Roorkee has announced a formal 'Go Live' for the implementation of its wave-I of ERP technology deployment. On the occasion, Prof Pradipta Banerji, director, IIT Roorkee, said, "We have become the first IIT in India to have chosen for operational digital transformation across our campuses. This ERP system will integrate some of the core functional aspects of our institute." Wave-II will be deployed next year. The technology has been provided by Atos, the digital services leader. "This ERP system is designed to simplify collaboration between various departments and their interdependence functionalities. With campus-wide deployment and upon completion of wave-I & II as planned, IIT Roorkee will be empowered to meet any future resource planning requirements faster, with a high degree of flexibly and better efficiencies," the institute said in a statement.

Virat Vaibhav ND 05.09.2016 P-09

लखनऊ स्थित नेशनल कॉलेज में चलेंगे आईआईटी बॉम्बे के कोर्स

वैभव न्यूज ■ लखनऊ

राजधानी स्थित नेशनल कालेज में आईआईटी बॉम्बे के 28 कोर्स संचालित होगें। यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होंगे जिनके रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा तक ऑनलाइन ही कराए जाएंगे। इसके लिए नेशनल पीजी कॉलेज और आईआईटी बाम्बे के बीच करार हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ एसपी सिंह ने बताया कि इन कोर्सेज के संचालन के लिए कॉलेज में 11 शिक्षकों की एक को-ऑर्डिनेटिंग कमिटी बना दी गई है। इन शिक्षकों के अर्न्तगत ही अभ्यर्थीयों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद छात्रों को लॉग इन नम्बर मिल जाएगा उसी के माध्यम से सभी स्टडी मटेरियल भी मुहैया कराया जाएगा। हर कोर्स की अवधि के बाद जिस भी छात्रों के लगे कि उसने कोर्स पूरा पढ़ लिया है तो वह परीक्षा दे सकेगा। यह जरूरी नहीं होगा कि सभी का परीक्षा साथ हो। कोई भी जब चाहे परीक्षा दे सकेगा। इसके लिए को-ऑर्डिनेटिंग कमिटी के शिक्षक से छात्रों को संपर्क करना होगा। उन्हीं की निगरानी में ही छात्र ऑनलाइन परीक्षा देगें। इसके बाद छात्रों को कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आईआईटी बाम्बे के स्टूडेंट ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के तहत इन कोर्सेज का संचालन किया जा रहा है। प्रिंसिपल ने बताया कि यह कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क होगा जिसे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट कर सकेंगे। शुरुआती चरण में अभी इसे कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के लिए शुरू किया गया है लेकिन भविष्य में इसे बाहर के छात्र के लिए चलाया जा सकता है।

Amar Ujala ND 05.09.2016 P-07

अब आईआईटी में होगी मेडिकल की पढ़ाई

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार और ग्लोबल ब्रांडिंग के उद्देश्य से आईआईटी ने पढ़ाई का तरीका बदला है। आईआईटी में इकोनॉमिक्स और कानून की पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो आईआईटी कैंपस में बैचलर ऑफ मेडिसिन (मेडिकल) की पढ़ाई भी होगी। आईआईटी खड़गपुर ने तो मेडिकल की पढ़ाई का खाका भी तैयार कर लिया है। आईआईटी कानपुर भी तैयारी में है।

आईआईटी कानपुर के पास काफी जमीन है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए फैकल्टी खोली जा सकती है। इस पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी सहमत है।

आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की दो दिवसीय (तीन-चार सितंबर) इंटरनेशनल कांफ्रेंस लॉ एंड इकोनॉमिक्स का समापन हुआ। आईआईटी कानपुर से पीएचडी करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शरदिंदु पांडेय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होती है। विदेशी विश्वविद्यालयों में हर फैकल्टी की पढ़ाई होती है। इसी वजह से भारतीय तकनीकी और प्रौद्योगिकी संस्थान पिछड़ जाते हैं। अब आईआईटी कानपुर ने इंजीनियरिंग और साइंस के साथ ही इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट (एमबीए) और लॉ की पढ़ाई पर जोर दिया है। इसका सकारात्मक नतीजा देखने को मिलेगा। आईआईटी की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी सुधार होगा।

- ग्लोबल ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार की वजह से पहल
- साइंस, इंजीनियरिंग के साथ ही इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, लॉ की पढ़ाई पर भी जोर

आईआईएम की फीस बढ़ सकती है

कानपुर (ब्यूरो)। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) की पढ़ाई महंगी हो सकती है। शैक्षिक सत्र 2016-17 से ही फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी की तैयारी है। ऐसा हुआ तो आईआईएम की फीस सालाना साढ़े 13 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगी। अभी सालाना फीस साढ़े 12 लाख के आसपास है। यह संभावना आईआईएम अहमदाबाद के डीन ऑफ फैकल्टी प्रो. एरोल डिसूजा ने जताई है। वह आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस लॉ एंड इकोनॉमिक्स में हिस्सा लेने आए थे।

फ्लिपकार्ट से वसूला जुर्माना

स्टूडेंटों को जॉब देकर ज्वाइनिंग न देने वाली ऑनलाइन मार्केटिंग की मल्टीनेशनल कंपनी फ्लिपकार्ट पर आईआईएम अहमदाबाद ने जुर्माना ठोका है। कंपनी ने मैनेजमेंट के नौ स्टूडेंटों को जॉब दी थी लेकिन चार महीने तक ज्वाइनिंग नहीं दी। इसके बाद कंपनी से बात की गई और सेलेक्टेड स्टूडेंटों को 80 फीसदी सैलरी (चार महीने की) बतौर जुर्माना देने का आदेश दिया गया। इस पर कंपनी तैयार हो गई। फ्लिपकार्ट ने दोबारा ऐसा किया तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा।

आईआईटी की पढ़ाई कोस्ट बेस्ड है। मुनाफा नहीं लिया जाता है। जो खर्च होता है, वही फीस के रूप में लिया जाता है। सत्र 2015-16 में फीस नहीं बढ़ाई गई थी। इस बार (2016-17) फाइनेंस कमेटियां फीस स्ट्रक्चर का रिवीजन कर रही हैं। जल्द ही नतीजा सामने आएगा। **-प्रो. एरोल डिसूजा, डीन ऑफ फैकल्टी, आईआईएम अहमदाबाद**

4 September

Deccan Herald ND 4/09/2016 P-4

'IITs are slaves of their own tradition'

NEW DELHI, PTI: The IITs are "slaves" of their own tradition and "orthodox", Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia said on Saturday, claiming these factors are major hindrances for the premier tech institutes towards attaining world class status.

Speaking at a seminar here, Sisodia cited the example of Malvika Joshi, who was rejected by IIT because as she does not have a 10th or 12th completion certificate, but was accepted by the prestigious Massachusetts Institute of Technology in the US.

"The institute which is given top status in India is orthodox. It is a slave of its own tradition, not willing to change, unwilling to become scientific. That is why it is India's top class, not the world's.

"We believe that only that person should get admission in IIT who has spent 20 years in school. This rigidity led IIT to lose one talented candidate. When I read about this girl the first thing that I thought was that is why IIT can never be the world's premier institute," Sisodia said.

"The election season is going on in the United States and debates are going as to who will be the Education minister or the Finance minister and the debate is between professors of top institutes, educationists.

Amar Ujala ND 4/09/2016 P-16

देश में नहीं है पेट्रोल-डीजल मिलावट की जांच करने वाली प्रयोगशाला

नई दिल्ली (ब्यूरो)। अभी देश में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो पेट्रोल और डीजल में हो रही मिलावट का पता लगा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह जवाब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस मामले में हाल ही में एक याची ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के अन्य हिस्सों में डीजल और पेट्रोल में अंधाधुंध मिलावट जारी है। इसके कारण न सिर्फ पर्यावरण का नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने एनजीटी में दाखिल किया हलफनामा

याची का आरोप, मिलावट से हो रहा पर्यावरण और लोगों की सेहत को नुकसान

एनजीटी में चेरूब सिंगला मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि देश भर में ईंधन में मिलावट का पता करने वाली जो भी प्रयोगशालाएं मौजूद हैं वह मानकों पर आधारित नहीं है। यहां तक कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और अन्य उच्च संस्थान भी ईंधन में मिलावट का सही परिणाम देने में सक्षम नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केवल आईआईटी मद्रास ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईंधन में मिलावट का पता करने के लिए सुविधाओं को विकसित करने में रुचि दिखाई है। वहीं इस मामले को जस्टिस स्वतंत्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने गंभीरता से लेते हुए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों में ईंधन की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके सदस्य अगली सुनवाई में ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हों। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

IIT-Kanpur to start online physics classes

http://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/IIT-Kanpur-to-start-online-physics-classes/articleshow/54001677.cms

KANPUR: An online physics course to be run by IIT-K for Indian as well as foreign students will begin from September 20. Even students based in UK, USA, UK, Singapore and other countries will also be able to take the online physics class. Prof HC Verma of IIT-K would conduct the classes.

The students will be able to study physics twenty-four hours through a website designed by the institute for this purpose. All queries of students will be replied online by Prof Verma.

"More than 2,000 students from class IX to class XII have also got themselves registered for attending online lectures for which no fee will be charged. A total of 24 lectures will be held in a span of eight weeks", Prof Verma said. He said that classes on physics would be taken on Tuesdays, Thursdays and Saturdays while on other days would be taught separate topics of the subject.

"Apart from India, students from USA, Singapore, Indonesia, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan and Australia have also shown interest in online physics lecture course. The highest number of students registered for this course are from USA", Prof Verma said. A total of 1,291 students from UP followed by Maharashtra, Bihar Telangana, Rajasthan, Karnataka and West Bengal have got themselves registered for taking the course, he added. He informed that registration for online lecture course, which had started on August 7, would continue till September 20 midnight. The classes would be held in English language, he added.

3 September

Business Line ND 3/09/2016 P-15

IIT Roorkee goes digital, deploys ERP tech

OUR BUREAU

New Delhi, September 2

Premier educational institute IIT Roorkee has embarked on a digital transformational journey by deploying Enterprise Resource Planning technology across all its three campuses.

This will enable an online system which the institute believes will add value to the transactions related to accounts payables/disbursements, assets, purchase orders, inventory management, general accounting entries, maintenance orders and projects, etc, it said in a statement.

Feather in the cap

Pradipta Banerji Director, IIT-R, said, "We add another feather in the cap of IIT-R by becoming the first IIT in India to have chosen for operational digital transformation across our campuses."

It has implemented Wave-I of the ADVAITA IIT Roorkee ERP Technology deployment and over a period of time and with completion of Wave-II next year with campus-wide integration, ADVAITA SAP ERP System would help IITR achieve a greater focus on analytics, better and quick decision-making, robust and accurate business information, the statement added.

Indian Express ND 3/09/2016 P-5

17 accredited labs don't have facility to check fuel adulteration, Petroleum Ministry tells NGT

ANEESHA MATHUR
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

NONE OF the 17 laboratories accredited with the Ministry of Petroleum and Natural Gas have the requisite facility to test petrol and diesel for adulteration, the Ministry informed the National Green Tribunal (NGT) Friday.

"It is stated that out of 20 labs, response from 17 labs (including IIT Delhi, IIT Madras and IIT Mumbai) was received. Except for IIT Madras, all the laboratories expressed their inability to detect the percentage of content of Naptha and Kerosene in case of adulteration of petrol and diesel, as currently they are not equipped with the requisite testing facilities," stated the affidavit filed by the Ministry.

In January, the NGT bench headed by Justice Swatanter Kumar had issued orders to the ministry to collect samples of fuel from various petrol pumps in Delhi and test them for adulteration, after a plea claimed that adulterated fuel was a major cause of air pollution in the capital.

In January, the Tribunal had constituted a committee comprising officials from the Central Pollution Control Board (CPCB), the Ministry of Petroleum and Natural Gas and state pollution control boards, to conduct joint inspection at 10 petrol pumps and analyse fuel samples in the laboratories of the state boards and the CPCB.

Taking a serious view of the affidavit, the NGT has now directed the members of the Committee to be present on September 14, the next date of hearing.

The NGT also directed the state governments to show how they had conducted tests for fuel adulteration earlier, and asked them to explain how action was taken against persons involved in fuel adulteration if basic testing facilities were absent.

IIT Madras, in its response to the Ministry, had said that while they have the facility to detect the presence of Naptha and Kerosene in a fuel sample, they do not have the equipment to test or quantify the percentage of adulteration.

The NGT's directions came in response to a plea by Delhi resident Cherub Singla, who had sought directions to inspect the quality of fuel at petrol pumps across the country, especially in cities facing acute air pollution.

In his plea, filed through advocate Avneesh Arputham, Singla had contended that fuel adulteration increases the emission of total hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides and particulate matter, thus adding to air pollution.

The petition had sought closure of petrol pumps and other agencies found dealing with adulterated fuels.

Dainik Bhaskar ND 3/09/2016 P-9

मेडिकल-आईआईटी में गरीब बेटियों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी

भास्कर न्यूज | रांची

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की किसी भी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए पैसे की कमी के कारण भटकना नहीं होगा। कोई भी बेटी मेडिकल और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सफल होती है तो उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 14वें स्थापना दिवस सह सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का शिक्षा पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है। इसे झारखंड में भी साकार किया जाएगा। लोग अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। क्योंकि शिक्षा से ही समाज और देश का विकास हो सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी एससी-एसटी स्टूडेंट एमबीबीएस करने के बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खोलना चाहता है तो सरकार उसे 50 लाख रुपए की मदद करेगी। उसके परिवार को पैसे के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इससे पहले उन्होंने इस साल मैट्रिक, इंटर, मदरसा, मध्यमा और वोकेशनल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 51 मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया।

Rashtriya Sahara ND 3/09/2016 P-9

हिंदी कंटेंट की कमी से 'स्वयं' के लांच में हो रही है देर

■ विनोद के शुक्ल

नई दिल्ली। एसएनबी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना 'स्वयं' के लोकार्पण में हो रही देरी के पीछे इस प्लेटफार्म पर हिंदी के कंटेंट की कमी है। मंत्रालय इसको दुरुस्त करने पर लगातार काम कर रहा है और जितनी जल्दी हिंदी की पठन सामग्री उपलब्ध होगी उतनी ही जल्दी इसे लांच कर दिया जाएगा। हालांकि मंत्रालय अपने स्तर पर इसे पूरी तरह से तैयार मान रहा है और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से समय मिलते ही इसे लांच कर दिया जाएगा।

मंत्रालय युद्ध स्तर पर जुटा काम में : इस प्लेटफार्म के माध्यम से वीडियो लेक्चर, रीडिंग मैटीरियल, सेल्फ एसेसमेंट टेस्ट और आनलाइन डिस्कशन फोरम उपलब्ध कराया जाना है। मंत्रालय इसके लिए ज्यादा से जयादा कंटेंट का अनुवाद लांच होने से पहले कराना चाहता है। वीडियो लेक्चर से पहले वाइस ओवर दिए जाने की बात मंत्रालय के अधिकारियों ने बताई। इस काम में दोनों तरह की सुविधाएं इस्तेमाल में लाई जा रही है मैनुवल और मशीन।

आईआईटी पटना को मशीन ट्रांसलेशन की महारत : इस काम को जल्द निपटाने के लिए मंत्रलय ने आईआईटी पटना की मदद लेने की बात

आईआईटी पटना करेगा मशीनी अनुवाद के माध्यम से मदद

वीडियो लेक्चर का वाइसओवर भी होगा हिंदी में मौजूद

स्वीकारी। आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. पुष्पक भट्टाचार्य ने बताया कि हम मशीन अनुवाद के माध्यम से 15 सालों से काम कर रहे है। अंग्रेजी से हिंदी, बंगला, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने पर देश भर की कई संस्थाओं में हम काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में मॉरफोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स होते है इसका मतलब एक ही वाक्य अलग-अलग तरह से होते है। इसलिए इसमें अधिक से अधिक डेटा तैयार करने का काम किया जा रहा है।

प्रो. भट्टाचार्य ने बताया कि ऑनलाइन कोर्स मटीरियल का अनुवाद करने के लिए मशीन और मानवीय मदद से एकसाथ काम किया जाएगा। मशीन ट्रांसलेशन मे जो गलतियां रह जाएंगी उन्हें मैनुअली ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी हमने पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम कर लिया है। एक बार किसी डोमेन में शब्दकोश फीड हो जाती है तो वह काम करने लगता है। भारतीय भाषाओं के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मैनुवली इतना अनुवाद करने में काफी वख्त लगेगा। इसलिए भी मशीन से अनुवाद किया जाना आवश्यक है और हम इसे त्रुटिहीन चाहते हैं।

बेहतर साधन से सर्वोत्तम उपलब्ध कराने की कोशिश : इसके लिए देश भर के 1000 से ज्यादा फैकल्टी को पहले ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा इस काम में सात राष्ट्रीय कोर्डिनेटर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं जिसमे इंजीनियरिंग के लिए एनपीटीईएल, परास्नातक के लिए यूजीसी, स्नातकों के लिए सीईसी, स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईआरटी और एनआईओएस, ड्रापआउटस के लिए आईजीएनओयू और मैनेजमेंट के लिए आईआईएमबी।

Follow IIT-K action plan to fight dust, govt tells pollution panel

http://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/Follow-IIT-K-action-plan-to-fight-dust-govt-tells-pollution-panel/articleshow/53987541.cms

GURGAON: The state urban local bodies department has made it mandatory for the Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) to follow an action plan given by experts from IIT-Kanpur to bring down dust pollution in the city.

The experts had conducted a study last year and prepared the action plan to bring down air pollution levels in Delhi-NCR cities, including Gurgaon.

According to the report, road dust contributes 38%, vehicles 20%, domestic fuel burning 12% and industries 11% to increasing the concentration of particulate matter (PM) 2.5 in the air. PM 2.5 are minute particles that can enter deep inside a person's lungs and trigger respiratory distress.

The report, a copy of which is with TOI, suggests stricter norms for construction and demolition sites. It recommends wet suppression, wind speed reduction (for large construction sites), proper disposal of waste, and covering of the construction and demolition sites to prevent pollution.

Interestingly, the report also held responsible fly ash emissions from coal power plants, hotels, restaurants and tandoor ovens for dust pollution. "These cause large emissions and thus need better management and proper fly ash disposal," the report says.

The experts have also urged for "implementation of BS VI (Bharat Stage (BS) VI regulation for vehicles), introduction of electric and hybrid vehicles, traffic planning and re-styroction of movement of vehicles, retrofitment in diesel exhaust, improvement in public transport etc" to control vehicular pollution.

HSPCB has also been instructed to conduct regular inspections of diesel generator (DG) sets. "Since small DG sets are used at the ground level and create nuisance and high pollution, it is recommended that all DG sets of size 2KVA or less should not be allowed to operate; solar power generation, storage and inverters should be promoted," says the report.

When contacted an HSPCB official in Gurgaon said, "We will make sure that all directions are implemented. Strict action as per law will be taken against defaulters."